और केवल उत्तराखण्ड की ही बात नहीं है, तमाम देश में, सभी जगहों पर उन की समस्याओं को हल न करने की वजह से एक असंतोष व्याप्त है और वह असंतोष अब फूट रहा है । हो सकता है कि आसाम की घटना से इस में और बढ़ावा मिल गया हो लेकिन यह पूरे देश में हो रहा है । उन की जो मांग उठ रही है, उस समस्या को ठीक-ठाक करने के लिए जब बंगाल की सरकार ने कोशिश की, तो उस में केन्द्रीय सरकार अपनी नाक क्यों घुसेड़ रही है और जबर्दस्ती दखलान्दाजी कर रही हैं, यह मैं जानना चाहता हूं । गृह मंत्री की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से जब वहां की सरकार इस मामले को ठीक करने में लगी हुई है . दखलान्दाजी क्यों की जा रही है जिस से समस्या और विस्फोटक बनती जा रही है ?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इस देश में पृथकतावादी प्रवृत्तियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लूगा, चूंकि और किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया, जो पृथकतावादी तत्व हैं जो कि पृथकतावादी आन्दोलन चलाते हैं, जो ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं ऐसे तत्वों के विरुद्ध जब राज्य सरकार कोई कार्यवाही करती हैतो क्या उसमें केन्द्रीय सरकार दखलन्दाजी नहीं करती है ? क्या यह बात सही नहीं है ?

चौथे, जो इन्फीलट्रेटर्स की बात कही जाती है कि बाहर से लोग आ रहे है और विदेशी शक्तियों के इशारे पर आ रहे है तो क्या यह सही है ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, it is most unfortunate that the hon. Member has not understood me properly. My statement is very clear. For his benefit and for the benefit of the House, let me tell you, Sir, that these Rajbanshis are also Rajput Tribes and the whole of Cooch-Behar they were previously ruling. (*Interruptions*) Sir, the hon. Member who was very eloquent about the Centre-State relations, should not advise me on this issue. I know my duties well and I know what is Centre-State relation. I have repeatedly said during my replies to the hon. Members that there is no intention on the part of the Central Government to interfere in the State affairs. We do not want to interfere and we do not want to take any action. On the contrary, it is the Central Government which has advised and helped the State Government in tackling this issue. Not only that. Whatever help is required is rendered by the Central Government and unnecessarily the hon. Member has made many allegations against me and my party also, which are far from truth. I do not accept it. (*Interruptions*). Sir, it is easy to make allegation but it is very difficult to prove it. Such allegations are made by the Marxists also. But there is no basis and there is no foundation for it.

---

**13.10 hrs.**

## MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR CREATING A NEW RAILWAY DIVISION AT SALEM (TAMIL NADU)

*SHRI C. PALANIAPPAN (Salem): Mr. Speaker, Sir, under the jurisdiction of Olavakkod Railway Division in Kerala State, 17250 railway workers are employed covering 1019 metres of railway track. Dharmapuri, Salem. Periyar. Coimbatore, the Nilgiris and Tiruchirapalli districts of Tamil Nadu are in this Olavakkod Railway Division. On 2-10-1979 a new Railway Division called Trivandrum Division has been created in Kerala State. The Railway track from Vettikattery to Cochin Harbour has been brought under this Division. Now in Kerala State there are two Railway Divisions, one at Olavakkod and the other at Trivandrum.

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri C. Palaniappan]

**18.10 hrs.**

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Upto 1956 in Podanur in Coimbatore district of Tamil Nadu there was a railway division. Since there was no Railway Division at that time in Kerala State, this Podanur Division was transferred to Olavakkod. As a large number of Railway workers living in the six districts of Tamil Nadu are to depend upon the dispensation of the Divisional Headquarters at Olavakkod, which is far away from their place of work, many times their grievances go unattended. Having realised their problems in 1963 itself, the Railway Board had acquired land in Kandampatti near Salem junction for the purpose of locating a new Railway Division at Salem. But the matter is resting there till today. Salem has become an industrial town. Salem Steel Plant is coming up fast. Just 50 kilometres away from Salem, in Mettur we have Mettur Aluminium Company, Mettur Chemicals Ltd. and many other large industrial undertakings. In Mohanur adjacent to Salem there is a cooperative sugar mill, a paper mill etc. These units have to go to Olavakkod for getting their wagon requirements registered. In the circumstanves explained, there is every need for creating a new Railway Division at Salem. I demand a statement from the hon. Minister of Railways in this regard.

(ii) ADVANCING OF FUNDS TO BAMNAN SUGAR MILLS AT GONDA (U.P.)

श्री आनन्द सिंह (गोंडा): बमनान शुगर मिल जिला गोंडा उत्तर प्रदेश की आर्थिक दशा जर्जर हो जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र के गन्ना किसानों और मिल मजदूरों का करोड़ों रुपया बाकी हो गया, जिस के कारण भारत सरकार ने दिनांक 13 मार्च, 1979 से मिल का अधिग्रहण कर मिल की संचालन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया और जिलाधिकारी गोंडा को कस्टोडियन नियुक्त कर दिया। तभी से यह मिल भारत सरकार की प्रबन्ध व्यवस्था में संचालित है।

मिल की आर्थिक दशा वर्ष 1978 में इस कदर खराब हो गई कि लगभग 80 लाख रुपया गन्ना किसानों का कई वर्षों का मिल पर बाकी रह गया जिस के फलस्वरूप किसानों में गन्ना उत्पादन के प्रति भारी उदासीनता उत्पन्न हो गई। मिल की आर्थिक दशा खराब होने से मिल मशीनों की मरम्मत का काम भी सीजन 1977-78, 1978-79 में ठीक प्रकार से नहीं हो सका।

इस बीच भारत सरकार ने जो भी धन दिया वह मिल के पुराने बकाए के भुगतान के लिए भी पर्याप्त नहीं रहा। सीजन 1979-80 के चलने के पहले जो भी धन दिया गया वह तब दिया गया जब मिल की मशीनों की मरम्मत का समय काफी गुजर चुका था। दिनांक 25 नवम्बर, 1979 को धन प्राप्त होने पर सामानों के मंगाने व मरम्मत शुरू कर सीजन चलाने की तैयारी होने लगी। मजबूरन इस क्षेत्र का पूरा गन्ना उत्तर प्रदेश केन कमिश्नर की पड़ोस की अन्य मिलों को देना पड़ा और जब दिनांक 1 जनवरी, 1980 को मिल चालू होने के लिए तैयार हुई तो जो गन्ना शेष बचा था उसी को पेर कर मिल को एक माह के अन्दर बन्द कर देना पड़ा।

इस वर्ष अधिकारीगण अगला सत्र चलाने के प्रयास में जुटे हैं किन्तु धन के अभाव में इस वर्ष भी यह कठिन दिखाई पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष भी धन समय निकल जाने पर ही प्राप्त होगा और मिल इस वर्ष भी समय से किसानों का गन्ना खरीदने में असमर्थ रहेगी।

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मिल के संचालन हेतु जो भी अग्रिम धन की आवश्यकता बताई गई है उसका तत्काल भुगतान दिलाने की व्यवस्था करने की कृपा की जाए ताकि किसानों एवं मजदूरों में एक विश्वास की भावना उत्पन्न हो और गन्ने के उत्पादन को बल मिले।

(iii) REPORTED NON-AVAILABILITY OF CEMENT IN BANGALORE AND OTHER PARTS OF THE KARNATAKA.

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is a matter of regret that for the past two or three months cement has become a rare commodity in Bangalore City and some other places in Karnataka. The public are put to great hardship for want of cement. Most of the buildings under construc-